छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा
चौदहवां सत्र

श्री ई.एस.एल. नरसिम्हन

राज्यपाल, छत्तीसगढ़

का

अभिभाषण

दिनांक 18 फरवरी, 2008

माननीय सदस्यगण,

नये वर्ष 2008 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस प्रथम अधिवेशन के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह प्रसन्नता और स्वस्थ संसदीय परंपरा के लिए गौरव का अवसर भी है क्योंकि राज्य गठन के बाद हुए प्रथम विधान सभा चुनाव एवं उपचुनावों में निर्वाचित होकर आये आप सब जनता के प्रतिनिधि इस वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।

2. मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप ऐसी योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया, जिनका लाभ समाज के सबसे जरूरतमंद और गरीब वर्ग को मिला। राज्य में सर्वांगीण विकास की जो पहल मेरी सरकार ने की, उसके क्रियान्वयन में ग्रामीणों किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा बच्चों को विशेष राहत देते हुए इन वर्गों के सशक्तीकरण के सार्थक कदम उठाए गए। देश के औद्योगिक विकास के मानचित्र में भी छत्तीसगढ़ को सशक्त उपस्थिति दर्ज करने में सफलता मिली है।

3. मेरी सरकार ने राज्य में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत, प्रत्येक गरीब परिवार को तीन रूपए प्रति किलो की दर से पैंतीस किलो चावल प्रति माह प्रदान करने के लिए आठ सौ सैंतीस करोड़ रूपये की लागत से एक क्रांतिकारी योजना लागू की है। इससे करीब चौंतीस लाख गरीब परिवारों की भूख की चिंता का समाधान हुआ है। चावल प्रदाय के लिए समूचे वितरण तंत्र में पारदर्शिता तथा निगरानी की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था की गई है। राशन सामग्री की निगरानी में प्रशासनिक अमले के साथ–साथ सामाजिक भागीदारी भी सुनिश्चित करने की ठोस पहल से इस योजना के क्रियान्वयन को सफल बनाया जाएगा।

4. मेरी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों के हित में एक और नया कदम उठाते हुए करीब साढ़े अट्ठायासी हजार बी.पी.एल. परिवारों को नौ सौ वर्ग फीट भूमि का आवासीय पट्टा देने के लिए 'दीनदयाल आवास योजना' शुरू की है।

5. गरीब परिवारों को अधिकाधिक निःशुल्क एकलबत्ती कनेक्शन देना तथा तीस यूनिट प्रतिमाह तक निःशुल्क विद्युत प्रदाय करना भी मेरी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय रहा है। विगत चार वर्षों में दो लाख तेरह हजार नए एकलबत्ती कनेक्शन दिए गए। वर्तमान में नौ लाख से अधिक एकलबत्ती कनेक्शनधारियों को प्रतिमाह पचास रूपये प्रति कनेक्शन के मान से पचास करोड़ रूपये से अधिक राशि की निःशुल्क बिजली दी जा रही है।

6. छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देने एवं राजकाज में उपयोग करने के लिए संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन लाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

7. प्रशासन को आम जनता के ज्यादा निकट लाने के लिए आदिवासी बहुल बस्तर अंचल में दो नए जिले नारायणपुर एवं बीजापुर प्रारंभ किए जा चुके हैं। उनचास विकासखंडों को तहसील बना दिया गया है। दो पंचायतों के पीछे पटवारी हल्के रखने के लिए एक हजार आठ सौ बीस नवीन पटवारी हल्कों का गठन किया गया। अब राज्य में पटवारी हल्कों की कुल संख्या चार हजार नौ सौ छह हो गयी है। छह सौ पचास पटवारियों के नवीन पद स्वीकृत कर भर्ती की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है। राजस्व प्रकरणों के निवारण में आम जनता को हो रही तकलीफों तथा विभिन्न योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए चार नए राजस्व संभाग भी गठित करने का निर्णय लिया गया है।

8. मेरी सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की वजह से छत्तीसगढ़ 'नो पावर कट वाला' देश का इकलौता राज्य बन गया है। लो–वोल्टेज तथा ओवर लोडिंग की समस्या से निदान के लिए राज्य गठन से लेकर अब–तक लगभग दो हजार करोड़ रूपए की लागत से विद्युत लाइनों सहित 220/132 के.व्ही. के सात, 132/33 के. व्ही. के तेइस एवं 33/11 के.व्ही के दो सौ अठ्यासी उपकेन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। उन्नीस हजार नौ सौ तीन वितरण ट्रांसफार्मर भी लगाए जा चुके हैं।

9. यह प्रसन्नता का विषय है कि मेरी सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का जो अभियान छेड़ा है, उसमें निरंतर नई सफलताएं मिल रही हैं। पन्द्रह सौ छब्बीस केन्द्रों में धान खरीदी की व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण किया गया तथा इसे प्रशासनिक कार्यालयों से भी जोड़ा गया, जिससे किसानों को धान विक्रय के साथ तुरंत ही चेक दे दिए गए। ऐसी व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ को हाल ही में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ ई–गवर्नेन्स का पुरस्कार भी दिया गया है। अब तक इकतीस लाख मीट्रिक टन से अधिक धान समर्थन मूल्य पर खरीद कर किसानों को दो हजार करोड़ रूपये से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। हर्ष का विषय है कि समर्थन मूल्य में धान खरीदी के मामले में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ राज्य, पंजाब के बाद देश में दूसरे स्थान पर रहा है।

10. मेरी सरकार की सोच और उसे लागू करने के प्रयासों की एक बानगी कृषि ऋण की प्रचलित दर तेरह–चौदह प्रतिशत को घटाकर छः प्रतिशत तक लाना भी है। इस निर्णय से प्रदेश के किसान जो पहले लगभग तीन सौ करोड़ रूपये तक का ऋण एक वर्ष में ले पाते थे, वे अब साढ़े छह सौ करोड़ रूपए तक का कृषि ऋण ले रहे हैं। शाकम्भरी योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को पचहत्तर प्रतिशत अनुदान पर अट्ठारह हजार पांच सौ पंप प्रदाय एवं पचास प्रतिशत अनुदान पर तीन हजार पांच सौ कूप खनन की सुविधा दी गई।

11. मेरी सरकार कृषि विकास दर में निरंतर वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सभी वर्ग के कृषकों को सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार हेतु आगामी वर्ष में पन्द्रह हजार नलकूप खनन तथा तीस हजार ड्रिप/स्प्रिंकलर की सुविधा देकर बयासी हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता हासिल की जाएगी।

12. आजादी के बाद से लेकर राज्य गठन तक पूरे प्रदेश के किसानों को मात्र बहत्तर हजार चार सौ कृषि पंपों में विद्युत कनेक्शन मिल पाए थे। जबकि विगत चार वर्षों में मेरी सरकार ने किसानों को तिरानवे हजार विद्युत कनेक्शन प्रदान किए हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना काल में प्रदेश में औसत कृषि विकास वृद्धि दर लगभग साढ़े सात प्रतिशत रही जो कि राष्ट्रीय औसत से तीन गुना अधिक है।

13. मेरी सरकार ने प्रदेश में किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज अदला बदली, बीज स्वावलम्बन तथा बीज उत्पादन के साथ–साथ वानस्पतिक ईंधन विकास योजना, गन्ना उत्पादन तथा जैविक खेती प्रोत्साहन हेतु नाडेप योजना का समावेश कर एक 'नवीन कृषक समग्र विकास योजना' लागू की है। वर्ष 2007–08 में प्रदेश में आधार एवं प्रमाणित बीज के उत्पादन में एक सौ तेरह प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। बीज उत्पादक कृषकों को राज्य योजना के तहत दलहन एवं तिलहन बीज हेतु पांच सौ रूपए प्रति क्विंटल उत्पादन अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। संकर किस्मों के बीज उत्पादन पर दो हजार रूपए प्रति क्विंटल एवं वितरण पर दो हजार रूपए प्रति क्विंटल अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

14. कृषकों को कृषि यांत्रिकीकरण का अधिकाधिक लाभ देने हेतु केन्द्र प्रवर्तित मैक्रोमैनेजमेंट योजना के तहत पावर टिलर तथा कृषि यंत्रों पर दिए जा रहे पच्चीस प्रतिशत अनुदान के बराबर पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा है।

15. किसानों को अनाज के अलावा अन्य लाभदायक फसलों के प्रति आकर्षित करने में भी सफलता मिली है। फल–सब्जी, मसाले, पुष्प, औषधि एवं सुगंधित फसलों के रकबे में लगभग तीन लाख हेक्टेयर की वृद्धि उत्साहवर्धक है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन पहले बस्तर,कबीरधाम,दुर्ग,बिलासपुर,कोरबा,रायगढ़ तथा सरगुजा में ही संचालित था, अब इसका लाभ रायपुर,राजनांदगांव जशपुर एवं कोरिया जिले को भी दिया गया है।

16. मछली पालन से डेढ़ लाख लोगों को स्व–रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य गठन के समय मात्र पच्चीस करोड़ मछली बीज उत्पादन हो रहा था, जो अब पैंसठ करोड़ से अधिक हो गया है। भारत में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आठवां बड़ा राज्य बन गया है। यहां अब करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होने लगा है। समन्वित मछली पालन के तहत अब तक दो हजार आठ सौ छियालिस इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं।

17. किसानों को आर्थिक संकट से राहत दिलाने के सिलसिले में एक बार फिर सिंचाई कर की कुल बकाया राशि का पचास प्रतिशत 31 मार्च, 2008 तक जमा किए जाने पर शेश पचास प्रतिशत राशि माफ करने का निर्णय लिया गया है। इससे दस लाख किसानों को छत्तीस करोड़ रूपए की छूट मिलेगी ।

18. मेरी सरकार द्वारा सिंचाई क्षमता बढ़ाने के प्रयास विशाल पैमाने पर किए जा रहे हैं। वर्ष 2007–2008 के बजट में ही जशपुर की ईब व्यपवर्तन योजना, सरगुजा की खुंटपाली व कासीसोत योजना, रायगढ़ की सपनई व्यपवर्तन योजना, महासमुंद की लोअर जोंक बराज तथा राजनांदगांव की मोंगरा बराज द्वितीय चरण परियोजनाएं ली गई हैं । इसके साथ ही वर्षों से लंबित घुमरिया बराज, सूखानाला बराज, कर्रानाला बराज मध्यम परियोजना एवं केलो वृहद परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, जिनके पूर्ण होने पर लगभग चालीस हजार तीन सौ सत्तर हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पिछले चार वर्षों में मेरी सरकार ने नौ लाख तिहत्तर हजार एकड़ से अधिक सिंचाई का रकबा बढ़ाया है, जिसके कारण प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत तेइस से बढ़कर तीस हो गया है।

19. अल्पकाल में कम लागत पर सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए मेरी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पांच सौ पन्चानवे एनीकट निर्माण की योजना की प्रगति विभिन्न स्तरों पर है । इसके तहत अब तक अड़सठ करोड़ रूपये की लागत से पचास एनीकट बनाए जा चुके हैं तथा दो सौ बयासी करोड़ रूपए की लागत से एक सौ बीस एनीकट निर्माणाधीन हैं। बीस मध्यम एवं दो सौ लघु सिंचाई योजनाओं के पुनरूद्धार एवं उन्नयन, जल उपभोक्ता संथाओं को सघन प्रशिक्षण जैसे अनेक कार्य भी किए जा रहे हैं ।

20. बिजली उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा कोरबा पूर्व में पांच सौ मेगावाट की परियोजना के अंतर्गत पहली इकाई अगस्त 2007 में लोकार्पित की गई और इसकी दूसरी इकाई का बॉयलर–लाइटअप भी दिसम्बर 2007 में किया जा चुका है। कोरबा पश्चिम में पांच से छह सौ मेगावाट क्षमता की, सरगुजा जिले के प्रेमनगर में तेरह सौ बीस मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना, भैयाथान में पन्द्रह सौ मेगावाट तथा मड़वा में एक हजार मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना के कार्य विभिन्न चरणों में हैं।

21. छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा इस वर्ष प्रदेश के सभी अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में सौर विद्युतीकरण करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। अभी तक तीन सौ छात्रावासों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण पूरा हो चुका है ।

22. रतनजोत के बीजों से बायोडीजल के उत्पादन की असीम संभावनाओं को देखते हुए ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं क्रेडा द्वारा भारत सरकार के उपक्रम इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश में सौ टन प्रतिदिन क्षमता के बायोडीजल संयंत्र लगाने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

23. पीने का शुद्ध पानी आम जनता को दिलाना भी मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हर्ष का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित राष्ट्रीय मापदंड ढाई सौ व्यक्तियों पर एक हैंडपंप के स्थान पर छत्तीसगढ़ में औसतन नब्बे व्यक्तियों पर एक हैंडपंप लगाने का काम पूरा किया जा चुका है।

24. मेरी सरकार जल प्रदाय योजनाओं के अमल में नगरीय निकायों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए अब तीस प्रतिशत अनुदान के स्थान पर सत्तर प्रतिशत अनुदान दे रही है। नल–जल योजनाएं तिरालीस नगरीय निकायों में क्रियान्वित की जा चुकी हैं, तीस निकायों में योजानाएं प्रगति पर हैं तथा शेष निकायों में आगामी वर्ष में कार्य प्रारंभ किया जाएगा। रायपुर नगर के लिए तीन सौ तीन करोड़ रूपए की योजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। अब तक करीब तीस हजार शालाओं में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है और शेष लगभग चार हजार शालाओं में निकट भविष्य में पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा।

25. मेरी सरकार ने विगत वर्ष बच्चों के लिए संचालित ''पूरक पोषण आहार कार्यक्रम'' को अधिक सार्थक एवं प्रभावी बनाने के लिए ''पका हुआ गर्म भोजन'' देने की नई व्यवस्था लागू की है, जिससे आंगनवाड़ियों में बच्चों की उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केन्द्रीय योजना आयोग ने पूरक पोषण आहार के इस मॉडल को उचित मानते हुए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसे लागू करने की अनुशंसा की है।

26. मेरी सरकार ने किशोरियों को आंगनवाड़ी केन्द्रों के नियमित हितग्राही के रूप में मान्यता देकर एक नई पहल की है,जिससे अब छह लाख किशोरियों को आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। विगत दो वर्षों में साढ़े चौदह हजार से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों की मंजूरी दी गई है।

27. आंगनवाड़ी कार्यकताओं को मिलने वाला मानदेय एक हजार रूपए से बढ़ाकर बारह सौ तथा सहायिकाओं को मिलने वाला मानदेय पांच सौ रूपए से बढ़ाकर छह सौ रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इनकी सेवाकाल में मृत्यु होने पर दस हजार रूपए की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान भी किया गया है।

28. गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह की समस्याओं के निदान हेतु 'छत्तीसगढ़ कन्या सामूहिक विवाह योजना' शुरू की गई है, जिसके तहत सामाजिक भागीदारी तथा शासकीय मदद से अब–तक दस हजार से अधिक बेटियों के हाथ पीले कराए गए हैं।

29. मेरी सरकार छह लाख पैंसठ हजार से अधिक जरूरतमंद निःशक्तजनों, वृद्धजनों,महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा,वृद्धावस्था तथा सुखद सहारा पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदान करती है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए समस्त बी.पी.एल. परिवारों के पैंसठ वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को भी पेंशन देने का निर्णय लेकर दो लाख दस हजार लोगों को लाभ पहुंचाने की पहल की गई है।

30. मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल अंचलों में विकास की गति बढ़ाने और स्थानीय जरूरतों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए बहुआयामी उपाय किये हैं। बस्तर, सरगुजा तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरणों के निर्णयों और उनके कारण करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रूपये लागत के कार्यों का असर अब दिखने लगा है। बीते एक वर्ष में करीब दो सौ हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों का उन्नयन इन अंचलों में हुआ है। इसी तरह एक वर्ष में करीब तीन सौ नए छात्रावास तथा करीब एक सौ तेरह आवासीय शालाएं खोली गई हैं। स्कूली शिक्षा की बेहतर सुविधाएं जुटाने के अलावा इन वर्गों के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने हेतु भी अनेक नये प्रयास किए गये हैं। विशेष शिक्षण केन्द्र, युवा कैरियर निर्माण योजना, एयर होस्टेस एवं पायलट प्रशिक्षण मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, मिनीमाता स्वावलंबन योजना, शहीद वीरनारायण सिंह स्वावलंबन योजना जैसी पहल का लाभ युवाओं को मिलने लगा है।

31. मेरी सरकार ने लोक आस्था केन्द्रों के विकास को भी प्राथमिकता दी है। आदिवासी अंचलों में अड़तीस सौ देवगुड़ी का जीर्णोद्धार किया गया। गिरौदपुरी में जैतखम्भ का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। गिरौदपुरी, भण्डारपुरी, सोनाखान आदि आस्था केन्द्रों में स्थानीय विकास की करोड़ों रूपये की योजनाएं संचालित की गई हैं। अब–तक साढ़े सात सौ मंगल भवनों को निर्माण से सामाजिक अधोसंरचना का विकास हुआ है।

32. मेरी सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम–2006 के तहत नियम बनाने को लेकर केन्द्र के समक्ष अपनी मांग पुरजोर ढंग से रखी थी और अब नियमों के अनुपालन हेतु तत्पर है। 13 दिसम्बर, 2005 तक वनभूमि पर काबिज करीब एक लाख बयानबे हजार व्यक्तियों को अधिकार पत्र प्रदान करने की तैयारी प्रगति पर है।

33. राज्य के वनों से वनवासियों के जीवन में विकास के नए रास्ते बनाने का काम मेरी सरकार ने कुशलता से किया है। संग्रहण वर्ष 2006 में तेन्दूपत्ता व्यापार के शुद्ध लाभ की सत्तर प्रतिशत राशि, लगभग साढ़े इकतीस करोड़ रूपए का भुगतान संग्राहकों को करने का कार्य अब समाप्ति पर है। संग्राहक परिवारों को प्रदान की जाने वाली चरण पादुका इस वर्ष महिला सदस्यों को देने का निर्णय लिया गया है। तेन्दूपत्ते की तरह लाख पालन को भी आय का जरिया बनाने के प्रयासों में एक बड़ी सफलता मिली है। विगत दो वर्षों में राज्य में लाख का वार्षिक उत्पादन अनठावन प्रतिशत बढ़कर देश में सर्वाधिक हो गया है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु रेशम कृमि पालन, बांस आधारित कुटीर उद्योग,दोना– पत्तल उद्योग, लघु औषधीय वनोपजों के प्रसंस्करण जैसे उपाय भी किए जा रह हैं।

34. राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरूआत भी छत्तीसगढ़ में कर दी गई है, जिससे बांस की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही, इसके उपयोग से कलात्मक वस्तुओं के निर्माण, कौशल वृद्धि से उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, विपणन आदि का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा और ग्रामीणों–वनवासियों को आय का एक और बेहतर जरिया मिल सकेगा।

35. मेरी सरकार ने श्रमिक कल्याण की दिशा में अनेक नवीन कार्य किए हैं। औद्योगिक न्यायालय की खण्डपीठ बिलासपुर में स्थापित की गई है। श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने भिलाई तथा कोरबा में कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के नवीन औषधालय प्रारम्भ कर दिए गए हैं। रायगढ़ में दो औषधालय तथा टेडेसरा–सोमनी (राजनांदगांव) में एक औषधालय शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। बीड़ी श्रमिकों के लिए राजनांदगांव डोंगरगढ़ एवं चपले (जिला रायगढ़) में आवास गृह बनाएं जाएंगे। रायपुर में 'हाइजीन लैब' की स्थापना की जा रही है।

36. मेरी सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण हेतु शीघ्र ही कल्याण बोर्ड की स्थापना का निर्णय लिया है। राज्य में गरीब परिवारों के लिए 'स्वास्थ्य बीमा योजना' भी शीघ्र लागू की जाएगी।

37. अच्छी सड़कों को राज्य की पहचान और सबकी प्रगति का जरिया बनाने के लिए मेरी सरकार ने वर्ष 2007–2008 में लगभग तीन हजार छह सौ किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया है। छियालीस वृहद पुल एवं ग्यारह मध्यम पुलों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। दो सौ चवालीस पुलों का कार्य प्रगति पर है। ए.डी.बी. योजना के अंतर्गत कुल तेरह सौ किलोमीटर सड़कों एवं पुलों के चौड़ीकरण तथा उन्नयन कार्य हेतु एक हजार दो सौ छियासी करोड़ रूपए की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत प्रथम चरण में आठ सौ ग्यारह किलोमीटर के नौ मार्गों का कार्य प्रगति पर है, इसके द्वितीय चरण में करीब तीन सौ पन्चानबे करोड़ रूपए की लागत के नौ मार्गों का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

38. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नौ हजार पचहत्तर किलोमीटर लंबाई की साढ़े सत्रह सौ सड़कें एवं साढ़े ग्यारह हजार पुल–पुलियों का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2007–2008 में एक हजार नौ सौ अठहत्तर करोड़ रूपए की लागत से छह हजार आठ सौ सैंतीस किलोमीटर की बारह सौ इनकानबे सड़कों का निर्माण किया जाएगा। जिससे राज्य की तीन हजार एक सौ बांसठ बसाहटें बारहमासी सड़कों से जुड़ जाएंगी।

39. कोरबा रेल्वे ओवर ब्रिज का कार्य पूर्ण हो चुका है व अन्य ग्यारह के कार्य प्रगति पर हैं। इस वर्ष दो नये आर.ओ.बी चकरभाटा, बिलासपुर एवं मोवा, रायपुर में प्रारंभ किए जा रहे हैं। शहरों में दो बायपास मार्ग बनाएं जा चुके है, सात कार्य प्रगति पर है, सकरी–तुरकीडीह बिलासपुर एवं रांवाभाटा–उरला रायपुर में निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है।

40. मेरी सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में बढ़ी यात्री परिवहन सुविधाओं का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य गठन के वक्त छत्तीसगढ़ में मात्र एक सौ सत्रह मार्गों पर राज्य परिवहन निगम एवं निजी व्यक्तियों के द्वारा दो हजार अट्ठारह यात्री वाहन संचालित होते थे, अब साढ़े बारह सौ मार्गों पर लगभग चार हजार यात्री वाहन संचालित हो रहे हैं।

41. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से विभिन्न वर्गों की आवासीय समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न नगरों में एक लाख बीस हजार रूपए से कम वार्षिक आय वाले लोगों के लिए राज्य प्रवर्तित 'दीनदयाल आवास योजना' के तहत दस हजार भवनों का निर्माण कर लिया गया है। दस हजार अतिरिक्त भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी तरह अटल आवास योजना, डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के माध्यम से लगभग बीस हजार मकान कमजोर तबकों के लिए बनाए जा रहे हैं। आवास क्षेत्र में आजीविका के नये अवसर देने के लिए राजमिस्त्री क्षमता विकास योजना बनाई गई है, जिसके तहत बीस हजार राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

42. 'नया रायपुर' परियोजना में कैपिटल कॉम्पलेक्स के अंतर्गत प्रथम चरण में दो प्रशासकीय भवनों, मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं सड़सठ किलोमीटर मार्ग का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया गया है।

43. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को वर्ष में न्यूनतम सौ दिनों का रोजगार दिलाने के लिए मेरी सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर ही है। सत्रह जिलों में अब तक करीब अठ्ठाइस लाख परिवारों का पंजीयन कर उन्हें रोजगार कार्ड प्रदाय किया जा चुका है। इस वर्ष मांग के आधार पर चौदह लाख अठ्हत्तर हजार परिवारों को रोजगार देने से छह सौ इन्कानबे लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किए गये। एक अप्रैल, 2008 से दुर्ग जिले में भी यह योजना लागू हो जाएगी।

44. 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्व–रोजगार' योजना के तहत चालू वर्ष में साढ़े छब्बीस हजार परिवारों को लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा साढ़े बावन करोड़ रूपए लागत की पांच विशेष परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर हैं।

45. केन्द्रीय पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का समुचित लाभ राज्य को प्रदान करने हेतु मेरी सरकार प्रत्यनशील है। इसके तहत स्थानीय संस्थाओं, पंचायतों एवं नगरीय निकायों में कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की जाएंगी। वर्तमान में तीस विकासखंड मुख्यालयों में पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा आगामी वर्षों में योजना में शामिल सभी विकासखंडों में पंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

46. एक लाख परिवारों को लाभ दिलाने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई नवा अंजोर परियोजना के तहत पन्द्रह हजार से अधिक समूहों के माध्यम से पच्यासी हजार से अधिक परिवारों को करीब एक सौ चौंतीस करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

47. गांवों में बुनियादी सुविधाएं जुटाने के लिए मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण निर्माण योजना, ग्राम विकास योजना, ग्राम गौरव योजना तथा ग्राम उत्कर्ष योजना संचालित की जा रही है। सीमेंट–कांक्रीट सड़क,

निर्मलाघाट, मुक्तिधाम, सद्भावना भवन,गोठान, कांजी हाउस तथा खेल मैदान निर्माण के कार्य बड़े पैमाने पर कराए गए हैं।

48. गांवों में सफाई और सेहत का वातावरण बनाने के लिए सभी जिलों में चार सौ तिरानबे करोड़ रूपये की लागत से संपूर्ण स्वच्छता अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बी.पी.एल. परिवारों हेतु चार लाख तथा ए.पी.एल. परिवारों हेतु तीन लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं। सोलह हजार शालाओं एवं चार हजार से अधिक आंगनवाड़ी भवनों में शौचालय का निर्माण हो चुका है। इस वर्ष नौ सौ तिरालीस निर्मल ग्राम पंचायतों तथा पांच निर्मल विकासखंडों का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है।

49. मेरी सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में पांच हजार से अधिक आबादी वाली चौहत्तर ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत पच्चीस लाख रूपये के मान से राशि दी गई है ताकि पंचायत राज संस्थाएं स्वयं के भवन तथा 'अटल बाजार' व्यावसायिक परिसर बनाकर आय बढ़ाने के स्थाई संसाधन विकसित कर सकें ।

50. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन आरक्षी केन्द्रों में करने की परिपाटी को बदलते हुए मेरी सरकार ने निर्णय लिया कि एक जनवरी, 2008 से ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीयन कार्य ग्राम पंचायतों में किया जाए।

51. मेरी सरकार ने नगरों के विकास तथा शहरी सुशासन पर विशेष ध्यान देते हुए एक वर्ष में अधोसंरचना मद में करीब दो सौ करोड़ रूपए की मंजूरी दी है। योजनाबद्ध विकास के लिए प्रत्येक शहर की दीर्घकालीन, अल्पकालीन एवं वार्षिक योजना तैयार कराई गई है। प्रत्येक शहर में सर्वसुविधायुक्त बाजार के निर्माण हेतु हाट–बाजार योजना शुरू की गई है। हर शहर की आवश्यकता के अनुरूप सांस्कृतिक भवन या मंगल भवन बनाए जा रहे हैं। शहरों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के बीस हजार बेरोजगारों को कुशाभाऊ ठाकरे युवा जन विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा।

52. मेरी सरकार ने राज्य में शिक्षा को जीवन स्तर उन्नयन और सर्वांगीण विकास का एक बड़ा माध्यम बनाया है। शालाओं में अभाव दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए हैं। विगत एक वर्ष में ही साढ़े सत्रह हजार से अधिक शिक्षकीय पदों की मंजूरी दी गई। राज्य में शिक्षाकर्मियों की भर्ती का एक ऐतिहासिक अभियान अभी जारी है, जिसके तहत स्वीकृत लेकिन रिक्त पदों पर लगभग तीस हजार शिक्षाकर्मियों की भर्ती की जा रही है। बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए चार सौ प्राथमिक विद्यालय, साढ़े चार सौ पूर्व माध्यमिक विद्यालय,डेढ़ सौ हाईस्कूल, चौरासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गए। लगभग ग्यारह सौ प्राथमिक शाला भवन तथा साढ़े चौदह सौ उच्च प्राथमिक शाला भवनों की मंजूरी दी गई है। तीन हजार प्राथमिक शालाओं, तेरह सौ उच्च प्राथमिक शालाओं, साढ़े पांच सौ से अधिक हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण की मंजूरी दी गई। साढ़े इकसठ लाख विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं को बीमा सुरक्षा दी गई है।

53. मेरी सरकार ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक बड़े कदम उठाए हैं। एक लाख छियासी हजार हाईस्कूल छात्राओं को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्र–छात्राओं तथा हाईस्कूल छात्राओं को लगभग पचास लाख सैंतीस हजार पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क प्रदाय की गई हैं। प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की छह लाख से अधिक बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश उपलब्ध कराया गया है। इन वर्गों की हाईस्कूल में पढ़ने वाली पैंसठ हजार से अधिक छात्राओं को निःशुल्क सायकलें प्रदान की जा चुकी हैं और अब जाति अथवा वर्ग से ऊपर उठकर सभी बी.पी.एल. परिवारों की बेटियों को इस योजना का लाभ देने का निर्णय भी मेरी सरकार ने लिया है।

54. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, एवं लोक निर्माण विभाग के सहयोग से इस वर्ष सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को विद्युत कनेक्शन, प्रकाश, पंखा तथा फर्नीचर की सुविधाएं देने का काम भी पूरा किया जाएगा।

55. शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की दिशा में मेरी सरकार लगातार प्रयासरत है। इन प्रयासों के तहत विगत एक वर्ष में आठ नई आईटीआई, बयालिस आईटीआई में अतिरिक्त व्यवसाय, छह आईटीआई का सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन तथा बीस आईटीआई में 'विश्वकर्मा योजाना' के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है। कबीरधाम एवं जांजगीर–चांपा में नवीन पॉलीटेक्निक प्रारम्भ किए गए। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और पॉलीटेक्निकों में बीपीएल छात्रवृत्ति योजना लागू की गई। प्रतिभावान छात्रों के लिए इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में शुल्क माफी योजना लागू की गई है।

56. मेरी सरकार ने उच्च षिक्षा की रोशनी आदिवासी अंचलों तक ले जाने को प्राथमिकता दी, इसके तहत दो वर्षों में जिन पन्द्रह नए महाविद्यालयों की मंजूरी दी गई, उनमें से ग्यारह आदिवासी अंचल में हैं। इसके अलावा अठ्ठारह महाविद्यालयों में अंग्रेजी लैब स्थापित की गई तथा ग्यारह महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर का दर्जा दिया गया। एक सौ उनचालीस महाविद्यालयों में कम्प्यूटर के पाठ्यक्रम शुरू किए गए। इस तरह उच्च शिक्षा और उसकी गुणवत्ता की बुनियादी जरूरतें तेजी से पूरी की जा रही हैं।

57. पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में एमबीबीएस की वर्तमान प्रवेश क्षमता को सौ से बढ़ाकर एक सौ पचास कर दिया गया है। जगदलपुर के बाद रायगढ़ में भी चिकित्सा महाविद्यालय खोला जा रहा है।

58. युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। रोजगार कार्यालयों का भी कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। शासकीय कार्यालय, निगम, मण्डल, प्राधिकरण, स्वशासी संस्थाओं आदि में भर्ती पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया गया है। इससे विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर नई भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

59. मेरी सरकार ने वर्ष 1997 तक के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का निर्णय लेकर पन्द्रह हजार से अधिक परिवारों के जीवन से अनिश्चितता का भय समाप्त किया है। इन कर्मचारियों को शासकीय सेवा की विभिन्न सुविधाएं मिलने लगेंगी और इनकी कार्यक्षमता बढ़ने का लाभ विभिन्न संस्थाओं को मिलेगा।

60. मेरी सरकार ने ग्राम पंचायतों द्वारा नियुक्त पंचायत कर्मियों को पन्द्रह सौ रूपए के मासिक मानदेय के स्थान पर विगत एक जनवरी, 2008 से दो हजार सात सौ से लेकर तीन हजार सात सौ रूपए का वेतनमान देने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। इसका लाभ प्रदेश के साढ़े सात हजार से अधिक पंचायत कर्मियों और उनके परिवारजनों को मिलेगा। इस तरह पंचायतराज संस्थाओं में इन कर्मियों का बेहतर योगदान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

61. मेरी सरकार ने उन्हीं निवेशकों को खनि–रियायतें स्वीकृत करने की नीति अपनायी है, जो प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग स्थापित कर वैल्यू एडीशन करें। राज्य में स्थापित स्टील तथा स्पंज आयरन की इकाईयों को एन.एम.डी.सी. के माध्यम से इस वर्ष पच्चीस लाख टन लौह अयस्क की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

62. प्रदेश के सुदूर एवं पिछड़े हुए खनिज धारित अंचल को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए मेरी सरकार ने जो सक्रिय और गम्भीर प्रयास किए उसके कारण बहुप्रतीक्षित दल्लीराजहरा–रावघाट–जगदलपुर रेल परियोजना हेतु राज्य शासन,एन.एम.डी.सी., स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल्वे के बीच एम.ओ.यू. किया गया। इस रेल परियोजना से पिछड़े अंचलों में सर्वांगीण विकास की रोशनी पहुंचेगी तथा दक्षिण भारत के लिए एक वैकल्पिक रेल मार्ग बनेगा।

63. मेरी सरकार की आकर्षक नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के मामले में विगत दो वर्षों से लगातार देश में प्रथम स्थान पर है। प्रत्येक जिले में कम से कम एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए कई जिलों में भूमि का चयन भी किया जा चुका है। सरगुजा, कबीरधाम तथा महासमुंद जिलों में छोटे औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने से वहां लघु श्रेणी के उद्योगों की स्थापना में सुगमता होगी।

64. मेरी सरकार ने हाथकघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कालातीत बैंक ऋण के कारण निष्क्रिय हो गई, बुनकर सहकारी समितियों के बैंक कालातीत ऋण माफ करने का निर्णय लिया। इससे पचहत्तर बुनकर सहकारी समितियां पुनर्जीवित हुई और साढ़े सात हजार बुनकरों को लाभ मिला है। शासकीय विभागों में हाथ करघा से निर्मित वस्त्र प्रदाय की योजना से बुनकरों की बिक्री बढ़ी है। बुनकरों के समग्र एवं आर्थिक विकास के लिए एकीकृत हाथकरघा विकास योजना रिवाल्विंग फण्ड, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, बेसिक इनपुट आदि योजनाएं लागू की गई हैं।

65. हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ हाट का निर्माण, कुम्भकारों को चाक प्रदाय योजना, ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना, टी.सी.पी.सी. बिलासपुर,कोंडागांव एवं किल्लेकोड़ा में सी.एफ.सी. की स्थापना,फ्यूजन स्कूल ऑफ आर्ट, रायपुर की स्थापना जैसे अनेक कार्य किए जा रहे हैं।

66 मेरी सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास में खेलकूद गतिविधियों को भी विशेष महत्व दिया है। साथ ही राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनकी योग्यतानुसार शासकीय सेवा देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खेल प्रतिभाओं का हौंसला बढ़ाने के लिए नगद पुरस्कारों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। राज्य में क्रीड़ा परिषद बनाने का निर्णय लिया गया है तथा खेल अकादमी का गठन भी राज्य शासन, किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अब पूर्णता की ओर है।

67. मेरी सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के साथ ही विभिन्न योजनाओं के अमल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नए प्रयासों के तहत विभिन्न सुदूर ग्रामीण अंचलों में दो सौ बहत्तर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, बीस होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी तथा एक सौ अठ्ठावन पैरामेडिकल स्टाफ की संविदा नियुक्ति कर ग्रामीण जनता को चिकित्सा सेवा का लाभ दिया जा रहा है। बिलासपुर जिले में सौ बिस्तर मानसिक रूग्णालय की स्थापना की जा रही है।

68. राज्य के कोने–कोने में बिखरी व असुरक्षित पुरातत्व महत्व की सामग्रियों को संग्रहित एवं सुरक्षित रखने के लिए मेरी सरकार द्वारा आदिवासी उपयोजना के अधीन निर्माणाधीन पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय को विश्व स्तरीय पर्यटन केन्द्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सिरपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में विकसित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राजिम मेला को कुंभ का दर्जा देते हुए इसे राष्ट्रीय पहचान दी गई है। महानदी के किनारे स्थित सभी पर्यटन महत्व के स्थलों का विकास किया जाएगा।

69. मेरी सरकार ने नई पर्यटन नीति लागू कर दी है, जिससे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके तथा पर्यटन के क्षेत्र में निजी पूंजी को आकर्षित किया जा सके। छत्तीसगढ़ में होटल प्रबंधन संस्थान को शीघ्र स्थापित कर इसमें स्नातक तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाये जाएंगे। दुर्ग–भिलाई में फूड इस्टीट्यूट खोलने के लिए आवश्यक पहल की जाएगी।

70. मेरी सरकार ने राज्य में कानून और व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस बल में मानव संसाधन तथा भौतिक संसाधनों में लगातार वृद्धि की है, जिसके कारण विभिन्न अपराधों सहित नक्सलवादी आतंक से निपटने में सफलता मिली है। विगत तीन वर्षों में पुलिस कर्मियों के लगभग साढ़े सत्रह हजार नये पदों का सृजन किया गया, जिससे राज्य का पुलिस बल साढ़े छब्बीस हजार से बढ़कर लगभग चवालीस हजार पहुंच जाएगा। पंद्रह नये पुलिस थाने एवं नौ नवीन पुलिस चौकियां स्वीकृत कर पुलिस को जनता के करीब लाने का प्रयास किया गया है। नक्सली हिंसा से निपटने के लिए विशेष स्टाक फोर्स का गठन किया गया

है। बीजापुर एवं नारायणपुर में नये जिलों तथा बस्तर एवं सरगुजा रेंज को मिलाकर करीब डेढ़ हजार से अधिक नगर सैनिकों के नये पद बनाकर भर्ती पूर्ण की गई है। थाना भवनों, चौकियों के अलावा सी.टी.जे.डब्ल्यू., कांकेर, पुलिस अकादमी, चन्दखुरी तथा विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों आदि का निर्माण कार्य प्राथमिकता से किया गया है। सभी नक्सल प्रभावित थानों,चौकियों,आउट पोस्ट की सुरक्षा मजबूत करने हेतु वायर फैंसिंग का कार्य प्रगति पर है।

71. मेरी सरकार ने बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ स्वस्फूर्त जनजागरण सलवा – जूडूम अभियान से प्रभावित आदिवासियों की सुरक्षा एवं पुनर्वास के समुचित प्रबंध किये हैं। नक्सलावाद से लड़ने का साहस रखने वालों के प्रति सरकार हमेशा सहायता हेतु संकल्पित है। शहीद विशेष पुलिस अधिकारियों के परिवारजन को दी जाने वाली अनुग्रह राशि दो लाख रूपये से बढ़ाकर पांच लाख रूपये की गई है।

72. मेरी सरकार ने न्याय प्रशासन को राज्य में सुदृढ़ बनाने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। राज्य के पच्चीस स्थानों में सिविल न्यायालयों तथा चौदह कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की गई है। न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। बिलासपुर के निकट ग्राम बोदरी में लगभग चौरासी करोड़ रूपए की लागत से उच्च न्यायालय का नया भवन बनाया जा रहा है।

73. सरकार की एक बड़ी उपलब्धि श्रेष्ठ जनभागीदारी प्रक्रिया अपनाते हुए राज्य का मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करना था, जिसके लिए उसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं योजना आयोग, भारत सरकार के सहयोग से 'राज्य योजना में मानव विकास का सुदृढ़ीकरण परियोजना' संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के आठ जिलों के मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किए जाएंगे।

74. 'यूरोपियन कमीशन–राज्य साझेदारी कार्यक्रम' के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका विकास हेतु साढ़े चार सौ करोड़ रूपए का अनुदान स्वीकृत हुआ है। जिसके तहत जनवरी, 2008 तक राज्य सरकार को कुल एक सौ अड़तीस करोड़ रूपए अनुदान मिल चुका है। प्रसन्नता का विषय है कि राज्य द्वारा प्रथम वर्ष किए गए कार्यों की सराहना यूरोपियन कमीशन ने की है।

75. छत्तीसगढ़ में तेज विकास तथा जनसुविधाओं में तेजी से वृद्धि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वॉन) का काम प्रगति पर है। नागरिक सेवाओं के विकेन्द्रीकरण हेतु चॉइस परियोजना का विस्तार पांच नए जिलों में किया जा रहा है। गांव–गांव में सामान्य सेवा केन्द्र खोलने की योजना है। मेरी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी को कुशल प्रशासन के साथ ही, पारदर्शिता तथा नागरिक सशक्तीकरण का माध्यम भी बनाना चाहती है।

76. छत्तीसगढ़ में चुनौतियों को अवसरों में बदलने की अदम्य इच्छा शक्ति मैंने देखी है। राज्य में चौतरफा विकास की गतिविधियों से यहां के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में नई आशा का संचार हुआ है। आप सबकी लगन, निष्ठा, परिश्रम, दूरदर्शिता समन्वय सद्भाव और सक्रिय योगदान से ही आम जनता की उम्मीदें पूरी होंगी। राज्य निरन्तर विकास के नए प्रतिमान स्थापित करे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़